[श्री हरुभाई मेहता]

5.00 म०प०

इसी प्रकार पंडित नेहरू ने भी कहा था और हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने भी कहा है कि निरस्त्रीकरण का महत्व विश्व विकास के प्रयासों से जुड़ा हुआ है। हथियारों के लिए किए गए सभी कोई भी प्रयासों से विकास अवरुद्ध होता है और इसीलिये हमें निरस्त्रीकरण समझौते के लिए समर्थन जुटाते रहना चाहिये। विभिन्न समस्याओं के बारे में—उदाहरण के तौर पर इजरायल के बारे में—सरकार की सजगता और तत्परता पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। इससे इजराइल द्वारा फिलिस्तीनियों पर किये गये हमले की भर्त्सना करने के बारे में सरकार की तत्परता और सहनशीलता का पता चलता है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के उप नेता की हत्या किये जाने की हमारी सरकार ने तत्काल ही भर्त्सना की। जब डेविस कप मैच खेलने के लिये हमारी टैनिस टीम को इजराइल भेजा जाना था तब मैंने सरकार को पहले ही लिख दिया था कि वहां की स्थिति को देखते हुए हमें वहां अपनी टीम नहीं भेजनी चाहिये ; तब सरकार ने इस बात की घोषणा करने में बड़ी ही तत्परता दिखाई कि वर्तमान स्थिति में हमारी टीम वहां नहीं जायेगी। इसी प्रकार उस समय हमारी क्रिकेट टीम को बंगलादेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी जब वहां के 21 विपक्षी दलों ने यह मांग की थी कि ऐसी स्थिति में क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित न किया जाये।

इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि हमारी विदेश नीति को, जिसकी सर्वत्र सराहना की गई है, और भी विकसित किया जाये। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह विश्व शांति के हित में हमारी विदेश नीति को तेज गति से कार्यान्वित करने के लिये प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री को बल प्रदान करे।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत लाभदायक वाद-विवाद हुआ और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण तथा रचनात्मक सुझाव दिए गए हैं तथा इस चर्चा में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले सभी सदस्यों को मैं बधाई देता हूं।

अपनी विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्यों के प्रति तथा जिस प्रकार हम अपनी विदेश नीति का संचालन करते हैं उस पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है। विस्तार पूर्वक चर्चा करते समय जो मतभेद उभर कर आये हैं, उनके बावजूद, हमारी विदेश नीति की मुख्य बातों की अनेक बार संपुष्टि की गई है तथा उनमें निष्ठा व्यक्त की गई है। आज भी विश्व में उसकी प्रमुख बातें प्रासंगिक हैं।

महोदय, गत दो या तीन वर्षों के दौरान विश्व में, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में, बड़ी तेजी से परिवर्तन हुआ है। नये दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है और नये-नये विचार उभर कर आ रहे हैं तथा इसके परिणामस्वरूप विश्व के सभी देशों के लिए चुनौतियां पैदा होंगी विशेषकर भारत जैसे देश के लिये, जो अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में, किसी को भी अतीत के दकदल में नहीं फंसा रहना चाहिये अपितु लचीला मार्ग अपनाना चाहिये। किन्तु इसके साथ-साथ हमें अपने उन मूल सिद्धांतों को नहीं छोड़ना चाहिये जिन पर हमारी विदेश नीति आधारित है।

जब हमने नैतिकता को अपनी विदेश नीति का आधार बनाया था तब हमें अनैतिक और अव्यवहारिक समझा गया था। आज स्थिति बदल गई है। अब विश्व अहिंसा की अनिवार्यता, परमाणु

अस्त्रों से छुटकारा पाने तथा निरस्त्रीकरण के महत्व को स्वीकार कर रहा है। आज विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि वास्तविक विकास तब तक संभव नहीं हैं, जब तक सच्चाई को गुट हितों और प्रभाव डालने वाले तत्वों से मुक्त नहीं कराया जाता। अब संसार हमारी इस विचारधारा के उत्तरोत्तर नजदीक आता जा रहा है कि विश्व के विभिन्न देश के लोगों की विविधताओं को बिना किसी स्वार्थ भाव के मानवीय आधार पर मान्यता प्रदान की जानी चाहिये और स्वीकार किया जाना चाहिये। जो देश शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के बारे में बहुत अधिक शंकालू थे, वे आज शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की बात कर रहे हैं न कि नफरत की।

उस समय से लेकर जब श्री जवाहर लाल नेहरू ने हमारी विदेश नीति को सुदृढ़ आधार प्रदान किया था, आज तक की अवधि के दौरान विश्व हमारी विश्व-धारणा के निकट आता रहा है। और यह सिद्ध होता है कि हाल ही में दिल्ली घोषणा द्वारा, जिस पर नवम्बर, 1986 में हस्ताक्षर किये गये थे, अहिंसा और परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति की पुष्टि की गई है। तर्क द्वारा परमाणु अस्त्रों के विकास को समाप्त करने पर जोर दिया गया है।

मई, 1984 में उस समय जब प्रमुख शक्तियों के बीच वार्ता में गतिरोध उत्पन्न हो गया था और जब कोई इस बारे में सोच ही नहीं सकता था कि तनाव समाप्त भी हो सकता है, तब इन्दिरा जी के साथ छः राष्ट्रों ने पहल की थी, किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रयास से और पांच महाद्वीपों के छह राष्ट्रों के सतत प्रयास से, उन सभी देशों के प्रयास से जो निरस्त्रीकरण में विश्वास रखते हैं, विश्व में सही वातावरण तैयार करके, हमने पहली बार आई० एन० एफ० संधि पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद परमाणु अस्त्रों को नष्ट किया जाना देखा था।

हमने देखा कि तनाव कम हो रहा है विशेषकर प्रमुख शक्तियों के बीच और वे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक प्रणालियों को मान्यता प्रदान करने लगे हैं। हमने पहली बार यह देखा कि सच्चा अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र विकसित हो रहा है और दो पोलों पर टिकी दुनिया अब आगे बढ़ने लगी है।

यही समय है जबकि हम अपनी इस धारणा को पूरा कर सकते हैं कि संसार में परमाणु अस्त्र नहीं होंगे और विश्व निरस्त्रीकरण की धारणा अपनायी जायेगी। हमें स्वयं को अस्त्रों की उसी दौड़ की स्पर्धा से बचाना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि परमाणु अस्त्रों के अलावा कोई ऐसा साधन विकसित न हो जिससे सब कुछ नष्ट न हो जाये। हमें यह भी सुनिश्चित करना है कि अस्त्रों की इस दौड़ में नये आयाम न जुड़ जायें। इसके साथ यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि पांच-महाद्वीपों में उच्च किस्म के किसी प्रकार के ऐसे अस्त्र का विकास न हो जाये जिसका कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक नुकसान किये बिना एक ही राष्ट्र के सम्पूर्ण नेतृत्व को समाप्त किया जा सके किन्तु जिसके कारण अभी अव्यवस्था पैदा हो जाए।

यह समय इस बात पर विचार करने का है कि हम इन सब चीजों को किस प्रकार नियंत्रित करें और इन्हें नई दिशा कैसे प्रदान करें। हमें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की नई व्यवस्था की आवश्यकता है। हमें एक वास्तविक कुशल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली बनाने की आवश्यकता है जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रजातंत्र और प्रभुसत्ता समानता का प्रतीक हो। हमें मानव मात्र के एक साझे परिवार की मान्यता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, जिसमें एक दूसरे के हित आपस में निर्भर हों

[श्री राजीव गांधी]

और दक्षिण में विकास के सहजीवन के साथ उत्तर में स्थायित्व हो। हमें गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के मूल्यों पर आधारित एक विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है।

महोदय, दक्षिण एशिया के सम्बन्ध में हमने कई अवसरों पर पाकिस्तान के साथ मैत्री और मधुर तथा सहयोगपूर्ण सम्बन्धों की बात दोहराई है। हमारे दिलों में पाकिस्तान के लोगों के प्रति-सद्भावनाएं हैं, जिनके साथ हमारी भाषा, संगीत और साहित्य साझा है। हमारा इतिहास साझा है। पाकिस्तान के लोगों के प्रति दुर्भावना नहीं है। हम उनका भला चाहते हैं। और इसीलिए हम लोगों के स्तर पर—यात्रियों, पर्यटकों, छात्रों, पत्रकारों, श्रमिक नेताओं, महिला ग्रुपों के आदान-प्रदान का स्वागत करते हैं। प्रत्येक स्तर पर हम और अधिक आदान-प्रदान चाहते हैं। हम पाकिस्तान की उस नई पीढ़ी के साथ, जिसका जन्म पाकिस्तानियों के रूप में हुआ, जिन्हें पाकिस्तान की नीतियों ने भारत की व्यक्तिगत रूप से जानकारी नहीं होने दी, आदान-प्रदान करना चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच शान्ति का अर्थ दोनों देशों के लोगों के बीच शान्ति है।

इन्हीं सम्बन्धों को बढ़ावा देने तथा सद्भावना पैदा करने के लिए हमने शिमला भावना से कई उपायों का प्रस्ताव किया है। मैं इसकी व्यापक सूची नहीं देना चाहता किन्तु मैं कुछ पढ़कर सुनाऊंगा। हमने शान्ति और मैत्री की एक सन्धि का प्रस्ताव किया है। हमने परमाणु सुविधाओं पर हमला न करने का प्रस्ताव किया। हमने सीमा सम्बन्धी नए बुनियादी नियमों पर चर्चा करने का प्रस्ताव किया है। हमने विमान अपहरण पर एम० ओ० यू० का प्रस्ताव किया है। हमने सैनिक विमानों द्वारा वायु सीमा का उल्लंघन करने के बारे में एम०ओ०यू० का प्रस्ताव किया है। हमने गैर-सरकारी व्यापार के विस्तार का प्रस्ताव किया है। हमने बिना भेद-भावपूर्ण व्यापार व्यवस्था कायम करने और एम० एफ० एन० सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है। भारत पाक संयुक्त उद्यमों को, लेखकों, बुद्धिजीवियों, संचार माध्यमों का आदान-प्रदान, सांस्कृतिक ग्रुपों का आदान-प्रदान, फिल्मों, ड्रामा, संगीत, तृप्य का आदान प्रदान करने को कहा है। हमने पुस्तकों, पत्रिकाओ और समाचार पत्रों के आदान-प्रदान का प्रस्ताव किया है। हमने विश्वास पैदा करने वाले तथा जोखिम को घटाने वाले अन्य कई उपायों का, जिन पर आपसी सहमति हो, प्रस्ताव किया है। हमने यात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्धों को हल करने का प्रस्ताव किया है। हमने नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने और आतंकवाद को समाप्त करने के क्षेत्र में भी सहयोग करने का प्रस्ताव किया है। दुर्भाग्यवश हमें पाकिस्तान से अत्यन्त असंतोषजन प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ है।

दूसरी ओर पाकिस्तान दोनों देशों के लोगों के बीच इन कार्यक्रमों को रोक रहा है। वह परमाणु हथियार कार्यक्रम पर ही जोर दे रहे हैं। उन्होंने सियाचिन जैसे क्षेत्रों में आक्रामक रुख अपना रखा है। वह अपने क्षेत्र में आतंकवादियों और पृथकतावादियों को सहायता और शरण दे रहे हैं। हमने पाकिस्तान से कहा कि हमारी सीमाओं पर आतंकवादी घटनाओं में हुई अचानक वृद्धि पर बातचीत के लिए भारत तथा पाकिस्तान के गृह सचिवों को बातचीत करनी चाहिए। दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बेहतर संचार सुविधा होनी चाहिए। सैनिक क्षेत्र में पहले से ही हाटलाइन है। शायद गृह सचिवों के बीच भी हाटलाइन की जरूरत है ताकि यदि कोई तनाव उत्पन्न हो तो उसे जितनी जल्दी संभव हो समाप्त किया जा सके। भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों के बीच एक हाटलाइन हुआ करती थी। किन्तु उनके अनुरोध पर इसे हटा दिया गया।

हम चाहते है कि इसे बहाल किया जाए ताकि यदि कोई तनाव हो तो उसे तुरन्त कम किया जा सके ।

मुझे आशा है कि हम अपने सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए ईमानदारीपूर्वक प्रयत्न करेंगे एक समृद्ध, स्थिर, स्वतंत्र, प्रभुसत्ता सम्पन्न तथा अखण्ड पाकिस्तान भारत के राष्ट्रीय हित में है । हम पाकिस्तान को इसी रूप से देखना चाहेंगे ।

पश्चिम में थोड़ा आगे, अफगानिस्तान में हम जेनेवा समझौते का स्वागत करते हैं । इससे अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की समाप्ति होगी । इससे शरणार्थियों की वापसी होगी जेनेवा समझौते से अफगानिस्तान में शान्ति और स्थायित्व का मार्ग प्रशस्त हुआ ये जिससे इसकी स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और गुटनिरपेक्षता को बल मिला है । हमने इसे सफल बनाने में खामोशी से अपनी रचनात्मक भूमिका अदा की है । हमें खेद है कि पाकिस्तान ने बातचीत के लिए हमारे निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया । इससे शायद काम थोड़ा और आसान हो जाता ।

हमारे विचार से अफगानिस्तान में शान्ति, स्थायित्व और गुटनिरपेक्षता की सर्वोत्तम गारंटी वहां पर सुदृढ़ सरकार का होना है । हम काबुल में एक सुदृढ़ सरकार देखना चाहेंगे । हमारा इसमें बहुत कुछ दाव पर है । इसीलिए हम राष्ट्रपति नजीबुल्लाह को समझौते के बाद की स्थिति के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए भारत यात्रा का निमंत्रण दे रहे हैं । हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए प्रगति, पुनर्निर्माण और पुनर्वास के युग की कामना करते हैं और हम इस प्रयास में उनका सहयोग करने का वचन देते हैं ।

महोदय, श्रीलंका के साथ हमारे समझौते का श्रीलंका में स्थायी और उचित समझौते के रूप में सभी ने स्वागत किया था, यह एक ऐसा समझौता था जिसमें तमिलों की सभी न्यायोचित जरूरतों और मांगों को पूरा किया गया था; एक ऐसा समझौता जो श्रीलंका की एकता को सुदृढ़ करता है, यह एक ऐसा समझौता था जो उसकी सुरक्षा सम्बन्धी सभी जरूरतों को पूरा करता था ।

पिछले 9 महिनों में भारतीय शान्ति सेना ने तमिलों और तमिलों के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया है । भारतीय शान्ति सेना ने तमिल उग्रवादियों और श्रीलंका की सेना के बीच के संघर्ष को समाप्त कर दिया है । 'लिट्टे' से हथियार ले लिए गए हैं—'लिट्टे' के एक बड़े वर्ग को भारतीय शान्ति सेना द्वारा निहत्था कर दिया गया है ।

उत्तर में लगभग शान्ति स्थापित हो गई है और पूर्व में भी स्थिति तेजी से सामान्य होती जा रही है । श्रीलंका की सरकार ने अधिकांश तमिल बन्दियों को रिहा कर दिया है और प्रान्तीय परिषदों के लिए विधान तैयार किया है । 'लिट्टे' के लिए हमारे द्वार खुले हैं । हम चाहते हैं कि वह राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा लें और लोकतांत्रिक तरीके से जोर आजमाइश करें ।

महोदय दक्षिण एशिया में 'दक्षेस' बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है । हम इसकी प्रगति से अत्यन्त संतुष्ट है । 'दक्षेस' नए आयाम स्थापित कर रहा है और दक्षिण एशिया में आपसी सम्बन्धों के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है । एक सदस्य ने 'दक्षेस' का इस्तेमाल द्विपक्षीय मामलों को सुलझाने का प्रश्न उठाया है । मैं अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं । 'दक्षेस' कोई

[श्री राजीव गांधी]

द्विपक्षीय मंच नहीं है और हम इसका इस्तेमाल द्विपक्षीय मामलों को हल करने के लिए नहीं करेंगे। हमारे सीधे सम्पर्क हैं और हम द्विपक्षीय मामलों को सीधे हल कर सकते हैं।

महोदय, हम चीन के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयत्न करते रहे हैं। हम विश्वास का वातावरण तैयार कर रहे हैं और अपने सम्बन्धों में एक नए और लाभकारी चरण की प्रत्याशा करते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि सम्बन्धों को सामान्य करने की प्रक्रिया जटिल है। सीमा सम्बन्धी प्रश्न पर शान्तिपूर्ण ढंग से बातचीत करने की आवश्यकता है। इसमें आपस में स्वीकार्य परिणामों की जरूरत है और हमें दोनों देशों की राष्ट्रीय भावनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत है। जब हम दीर्घावधिक समझौते की बात करते हैं तो उसके लिए हमारी सीमाओं पर शान्ति बनाए रखना जरूरी है। हम चीन के साथ बहुत से क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि सम्बन्धों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया का इस सदन के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। हमने सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार कर लिया है कि उनके नियन्त्रण पर मुझे चीन यात्रा पर जाना चाहिए।

जापान के साथ हमारे सम्बन्धों में काफी प्रगति हुई है। मैंने उनके भूतपूर्व प्रधान मंत्री नाकासोने, जब वह प्रधान मंत्री थे, काफी बातचीत की है। और जापान की इस यात्रा के दौरान मैंने प्रधान मंत्री ताकेशिता के साथ काफी लम्बी बातचीत की है। जापान इस समय हमारे आधिकारिक विकास सहायता का सबसे बड़ा दाता है। यह हमारा तीसरा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। हम जापान के साथ अपने संयुक्त उद्यमों में, जापान के साथ तकनीकी सहयोग में जापानी निवेश में वृद्धि की आशा करते हैं।

जापान से वापस आते समय, मैं वियतनाम में उनके नए नेताओं से मिलने के लिए रुका। वियतनाम भारत का सच्चा मित्र है, जिनके साथ हमारे साझे मूल्य हैं, साझे सिद्धान्त हैं और बहुत सी साझी भौगोलिक राजनैतिक मान्यताएं हैं। मेरी यात्रा से दोनों देशों के बीच के सुदृढ़ ऐतिहासिक सम्बन्धों में पुनः विश्वास प्रकट किया गया। हमने वियतनात के नेताओं के साथ एक सुदृढ़ राजनैतिक सूझबूझ स्थापित कर ली है, एक ऐसी सूझबूझ जिससे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा एशिया में शान्ति और स्थायित्व की ताकतें मजबूत होंगी।

हमने कम्पूचिया के बारे में बातचीत की। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कम्पूचिया की समस्याओं का हल खोजने के प्रयत्नों में सक्रिय रहा है। हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आशा करते हैं कि प्रिंस सिहानुक और प्रधान मंत्री हुन्सेन के बीच शीघ्र बातचीत होगी।

ए० एस० ई० ए० एन० देशों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे आशा है कि वह आगे आएंगे और अपनी भूमिका अदा करेंगे। ए० एस० ई० ए० एन० देशों के साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हो रहा है। हमने आर्थिक, वाणिज्यिक और अन्य सम्बन्धों को बढ़ाया है। सिंगापुर के प्रधान मंत्री कुछ समय पहले भारत आए थे और मैं इण्डोनेशिया और मलेशिया गया था। मलेशिया के साथ हमारे बहुत पुराने सम्बन्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, खाड़ी युद्ध जारी है। हमने दो गुट-निरपेक्ष देशों के बीच इस भ्रातृघातक संघर्ष पर लगातार खेद प्रकट किया है। हमने दोनों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा है। हमने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 598 का समर्थन किया है। शहरों के बीच पुन: युद्ध शुरू होने और उसमें रासायनिक हथियारों का उपयोग किये जाने में उक्त संकल्प को लागू करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया को कम महत्व दिया गया है। हम महा शक्तियों की नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि होने पर खेद प्रकट करते हैं। अमरीकी युद्धपोतों के सम्मिलित हो जाने से खाड़ी में होने वाली घटनाएं अधिक से अधिक गम्भीर हो रही हैं और हम चारों तरफ अधिक से अधिक संयम रखने का अनुरोध करते हैं। समय की पुकार है कि राजनेता की तरह सावधान रहे, नौसैनिक उपस्थिति में वृद्धि को रोका जाए और बातचीत द्वारा समझौते को बढ़ावा दिया जाय।

पश्चिम एशिया में, फिलिस्तीनियों के उद्देश्य और पी० एल० ओ० के प्रति हमारा समर्थन ऐतिहासिक और अनुकूल है और यह हमारे स्वतंत्रता संघर्ष से भी बहुत पहले का है। हम अधिकृत क्षेत्रों में इजरायली सेनाओं के बर्बर व्यवहार की भर्त्सना करते हैं। हाल ही में अबु जिहाद की निर्मम हत्या भी एक ऐसा कार्य है जिससे उस क्षेत्र में केवल तनाव ही बढ़ेगा और इन मामलों को सामान्य बनाने तथा उनका हल ढूंढने में और अधिक कठिनाई होगी। स्थिति बहुत ही गम्भीर है और उसे थोड़ा-थोड़ा करके हल नहीं किया जा सकता। मेरा विश्वास है कि मध्य-पूर्व के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए समर्थन बढ़ रहा है। फिलिस्तीनियों का आत्म निर्णय के लिए अहस्तान्तरकरणीय अधिकार है और हम उस अधिकार के लिए उनका समर्थन करते हैं।

मध्य अमरीका के सम्बन्ध में हम 'कोन्टेडोरा' प्रक्रिया का समर्थन करते हैं। इसी वजह से गत वर्ष के मध्य में गुआटेमाला शांति समझौता हुआ है, जिससे न्यायोचित और स्थायी समझौता होना चाहिए, जिससे क्षेत्र के सभी राज्यों के लिए बाहरी हस्तक्षेप और दखल के बिना आत्म-निर्भय, स्वतंत्रता, सुरक्षा और अखण्डता का अधिकार सुनिश्चित हो सके।

लेटिन अमरीका के भारत से बहुत दूर होने के बावजूद भी उसके भारत के प्रति बढ़ते हुए स्नेह, एक दूसरे के प्रति बोध और ठोस समर्थन कई बहुत से साक्ष्य हैं। मैं डेनियल ओरटेगा द्वारा निकारागुआ में शांति लाने, निकारागुआ की स्वतंत्रता को बनाए रखने तथा उस क्षेत्र में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को मजबूत बनाने के लिए किए गए उचित प्रयासों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

गत वर्षों के दौरान पेरू के साथ हमारे सम्बन्धों में भारी सुधार हुआ है। लेटिन अमरीका में पेरू एक नए रास्ते का डंका पीट रहा है। अर्जेंटीना और मैक्सिको, हमारे छः राष्ट्रों की पहल में हमारे साथी हैं और हम एक साथ मिलकर निशस्त्रीकरण के लिए कार्य कर रहे हैं। आयात निर्यात शुल्क और व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार वार्ताओं में ब्राजील और भारत के बीच काफी सहयोग है और हमारी एकता तथा समरुचि होने के कारण हम अपने रास्ते पर चल सके हैं और विकासशील देशों के पक्ष में बहुत सी बातें कर पाए हैं। हमें लेटिन अमरीका के साथ अपना सहयोग उस स्तर तक बढ़ाना चाहिए जोकि लेटिन अमरीका से भारत के लिए अधिक कार्य और सहानुभूति के अनुरूप हो।

सोवियत संघ के साथ हमारे सम्बन्ध परम्परागत रूप से निकट और हार्दिक रहे हैं। इनमें अब अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है, इनमें नए स्तरों तक गुणात्मक सुधार हो रहा है। बढ़ते

[श्री राजीव गांधी]

हुए व्यापार और आर्थिक सहयोग में नई वृद्धि और विशेष रूप से हम जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो सहयोग शुरू कर रहे हैं इसका विशेष उल्लेख करना चाहिए। सोवियत संघ में भारत महोत्सव और भारत में सोवियत महोत्सव काफी सफल रहे हैं। हम इस वर्ष नवम्बर में महासचिव गोर्बाचेव के भारत आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इन्दिरा जी के 1982 में अमरीका का दौरा करने के बाद हम अपने द्विपक्षीय सम्बन्धों में लगातार सुधार कर रहे हैं। अब अमरीका व्यापार में हमारा सबसे बड़ा भागीदार है जिसमें आर्थिक सहयोग और प्रौद्योगिकी अन्तरण का अवसर बढ़ रहा है। हम अमरीका के साथ अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विषयों पर लाभप्रद विचार विमर्श कर रहे हैं। रक्षा मामलों के बारे में हम उच्च प्रौद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं जिससे हम अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर सकें।

हमारी विदेश नीति गांधीजी द्वारा हमें दी गई एक मानवता, अहिंसा और सच बोलने के बुनियादी अभिकरण पर आधारित है। हमने मानवता के बारे में, हमने जो संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर अपने आपको विभाजित कर दिया है उसे समाप्त करने के लिए संघर्ष किया है। हमने रंग-भेद को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया है जिससे नामीबिया में उपनिवेशवाद पैदा हुआ है। हमने रंगभेद के कारण दक्षिण अफ्रीका में हमले, विद्रोह और अस्थिरता के विरुद्ध संघर्ष किया है। इस चुनौती के प्रति हमारी प्रतिक्रिया का अफ्रीकी कोष से पता चलता है। 45 देशों ने इसका उत्तर दिया है और उसमें हमारी ओर से 50 करोड़ रुपए सहित एक चौथाई बिलियन डालर का वचन दिया गया है। भारत सहित बहुत से दानी देशों ने परियोजनाओं को अधिक से अधिक मान्यता देनी शुरू कर दी है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की विश्व में मान्यता बढ़ रही है। किसी समय इसको अनैतिक कहा जाता था : आज इसे सभी राष्ट्रों द्वारा स्वीकार किया जाता है। गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सिद्धान्त और प्रथायें विश्व में सुनिश्चित शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए केवल रास्ते के रूप में देखी जाती है। हम छोटे अल्पमत से पूर्ण बहुमत में हो गए हैं और उन देशों के भी, जो, यहाँ तक कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में नहीं हैं, गुट-निरपेक्ष भाषा में बात करना शुरू कर दिया है। हमें इस आन्दोलन की एकता को अवश्य बनाए रखना चाहिए क्योंकि इसी से हमें शक्ति मिलेगी।

आर्थिक क्षेत्र में, असंगत विश्व व्यवस्था दक्षिण में विकास को नुकसान पहुंचा रही है और उत्तर में लगातार खुशहाली पैदा कर रही है। हमें आर्थिक व्यवस्था के बारे में एक नई सर्वसम्मति की आवश्यकता है, विकास के सम्बन्ध में एक नई सर्वसम्मति और सहकारी विश्व व्यवस्था की आवश्यकता है।

भारत निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए उस समय से संघर्ष करता रहा है जबकि वे प्रचलित नहीं थे। आई०एन०एफ० संधि इस प्रक्रिया में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन यह अवश्य याद रखना चाहिए कि यह केवल पहला कदम है। और अधिक कुछ किये जाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में और अधिक कुछ बनेगा और अधिक प्रगति करने के लिए हमें समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। हमें इस प्रक्रिया में सभी परमाणु हथियार वाली शक्तियों को सम्मिलित करना

चाहिए। हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि हथियारों, परमाणु हथियारों का नए क्षेत्रों में विस्तार न हो। हमें यह देखना चाहिए कि जन संहार के अन्य हथियारों अथवा शस्त्र हथियारों का और विकास न हो। हमें भय दिखाकर निवारण करने वाले सिद्धान्तों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्तों में बदल देना चाहिए।

वर्ष 1988 में, हमने भारत की स्वतन्त्रता के 40 वर्ष पूरे किये हैं। हमने अपनी विदेश नीति के निर्माता जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी भी शुरू कर दी है। उनकी दूरदृष्टि थी जिसे उनकी मृत्यु के 25 वर्ष बाद विश्व-व्यापी मान्यता मिल रही है। हम प्राचीन सभ्यता के स्वाभिमानी उत्तराधिकारी हैं जिसके बुनियादी निर्देश हमारी विदेश नीति के स्त्रोत हैं। हम जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता के प्रति दृढ़ निश्चयी रहे हैं। हमारे सामने नई चुनौतियां और नए आसार तथा नई संभावनायें हैं। हमें अपने सिद्धान्तों का पालन करना होगा लेकिन हमें उन्हें नए तरीके से समझना होगा जोकि हमारे सामने उत्पन्न परिस्थितियों के अनुरूप हो। हम अपने पड़ोस में शांति और सौहार्द के लिए और क्षेत्रीय संघर्षों के प्रस्ताव के लिए कार्य करेंगे, हम विश्व में मानव अधिकार और न्याय के लिए, एक जैसे प्रभुसत्ता सम्पन्न राष्ट्रों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय लोकतंत्र के लिए, सहकारी विश्व व्यवस्था के लिए एक मानव-जाति के लिए कार्य करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगों के साथ प्रस्तुत सभी कटौती प्रस्तावों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विदेश मंत्रालय से सम्बन्धि अनुदानों की मांगें सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1988-89 के लिए विदेश मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें।

मांग संख्या	मांग का नाम	18 मार्च 1988 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
23	विदेश मंत्रालय	69,26,00,000	15,50,00,000	334,72,00,000	77,50,00,000